यूपी सहित 16 राज्यों में ब्रॉडबैंड के लिए 19 हजार करोड़ का बजट

कैबिनेट की मुहर...डिजिटल इंडिया के लिए पीपीपी मॉडल, विद्युत क्षेत्र को तीन लाख करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश के सभी गांवों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने पीपीपी मॉडल पर मुहर लगाई है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारत नेट परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों में ब्रॉडबैंड सिस्टम पहुंचाने के लिए 19,041 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 16 राज्यों के लगभग 3,60,000 गांवों को कवर करने के लिए कुल 29,430 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार के 19,041 रुपये के हिस्से को बैठक में मंजूरी दी गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, असम, सहित 16 राज्यों को मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इस सेवा से जोड़ा जा चुका है। अगले 1000 दिनों में देश के छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ दिया जाएगा। सरकार जल्द ही अन्य राज्यों को भी इसी आधार पर सुविधा का लाभ देगी। इस प्रोजेक्ट को 9 पैकेजों में बांटा गया है और किसी भी कंपनी को 4 से अधिक पैकेज रखने की अनुमति नहीं होगी।

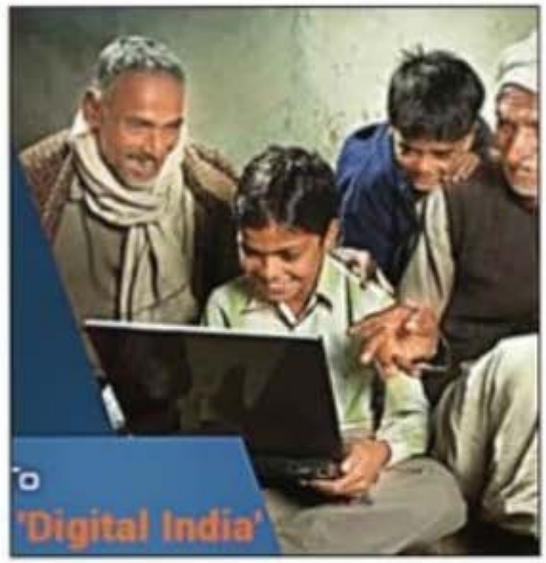

3.60 लाख गांवों को कवर करने के लिए 29,430 करोड़ रुपये

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण तारीख बढ़ी

कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की तारीख को 30 जून से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इसके कारण पहले से अनुमानित 58.5 लाख रोजगार की तुलना में 71.8 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। सरकार बीती 18 जून तक इस मद में प्रतिष्ठानों को 902 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है। इस योजना में 22,998 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़

सरकार की योजना पूरे देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य सरकारों से इस संबंध में प्लान मांगा जाएगा। विद्युत मंत्री आरके सिंह ने बताया कि बड़े शहरों में ऑटोमेटिक सिस्टम लागू होगा। पुरानी एचटी-एलटी लाइन बदली जाएंगी। गरीबों को प्रतिदिन रिचार्ज की सुविधा दी जाएगी। देशभर में मांग के अनुरूप प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

वित्त मंत्री की घोषणा पर भी मुहर... *कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री की ओर से कोरोना के कारण 6.28 लाख करोड़ की मदद पर भी सहमति दी गई है। इसके अलावा इस साल नवंबर तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए 93 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है।*